THE HINDU

Supreme Court, in a majority verdict, upholds constitutional validity of EWS quota

November 07, 2022 11:05 am | Updated 09:07 pm IST

A Constitution Bench of the Supreme Court on Monday, in a 3:2 majority decision, upheld the validity of the 103rd Constitutional Amendment which provides 10% reservation in government jobs and educational institutions to the 'economically weaker sections of the society but excludes the 'poorest of poor' among Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), Socially and Educationally Backward Classes (SEBC) and Other Backward Classes (OBC) from its scope.

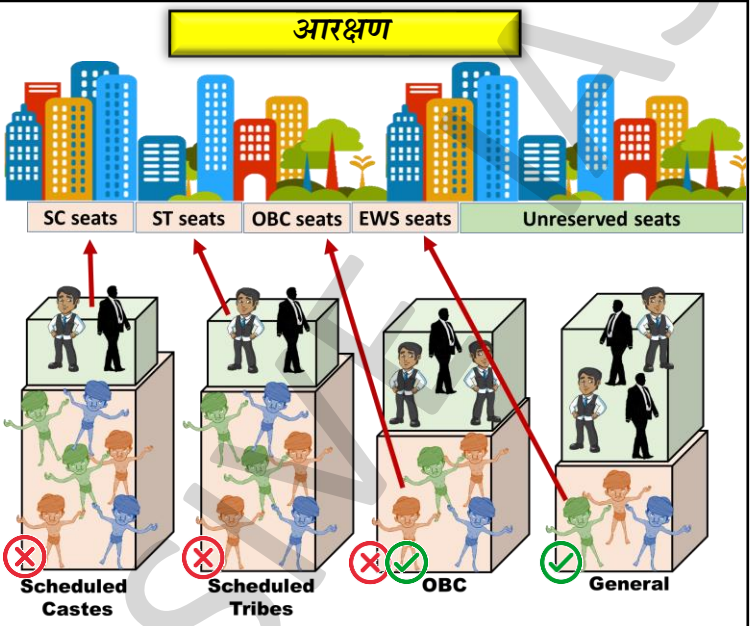

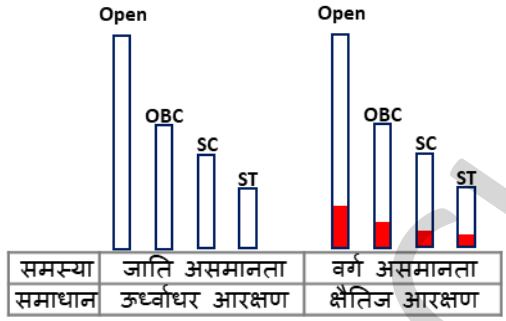

ऊर्ध्वाधर आरक्षण का उदाहरण

- 15% SC, 7.5% ST, 27% OBC, 10% EWS

क्षैतिज आरक्षण का उदाहरण

- PwDs के लिए शिक्षा में 5%, नौकरियों में 4%

सामान्य वर्ग के गरीब EWS आरक्षण द्वारा वर्ग असमानता से लड़ते हैं
OBC के गरीब क्रीमीलेयर को बाहर कर वर्ग असमानता से लड़ते हैं
SC/ST के गरीबों के पास वर्ग असमानता से लड़ने का कोई साधन नहीं है
इसलिए लोगों की मांग थी कि EWS क्षैतिज आरक्षण के रूप में होना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा व्यवस्था को 3:2 के बहुमत से बरकरार रखा है

सिन्हो आयोग 2010 गरीबी एक सामाजिक-आर्थिक समस्या है, आरक्षण सामाजिक-आर्थिक मापदंड/आधार पर होना चाहिए।

आरक्षण

नौकरियां / शिक्षा

- अनुसूचित जाति
- अनुसूचित जनजाति
- अन्य पिछड़ा वर्ग
- ईडब्ल्यूएस

लोक सभा/ राज्य विधानसभा

- अनुसूचित जाति (जनसंख्या अनुपात)
- अनुसूचित जनजाति (जनसंख्या अनुपात)
- ~~एंग्लो-इंडियन (मनोनीत)~~

अनुच्छेद	आरक्षण का प्रावधान
15 (4),(5)	शिक्षा में
16 (4)	सरकारी जॉब में
16 (4A)	पदोन्नति में
243D	पंचायतों में
243T	नगर पालिकाओं में
330	लोक सभा में
332	विधानसभाओं में

आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है अनुच्छेद 15 और 16, सरकार को आरक्षण देने के लिए सशक्त (न की बाधित) करता है।

The NEWS Minute — Support us

EWS judgement does not compel states to implement 10% quota

The Union government had, in 2020, said that it was the states' prerogative whether they wanted to implement EWS quota or not.

NEWS EWS QUOTA | MONDAY, NOVEMBER 07, 2022 - 19:18

THE HINDU

Right to reservation is not a fundamental right, observes SC judge as parties withdraw plea for quota

June 11, 2020 11:36 pm | Updated June 12, 2020 04:53 am IST - NEW DELHI

अनुच्छेद 46 (भाग-IV डीपीएसपी)

- सरकार कमजोर वर्ग के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगी
- इसलिए, सरकार अनुच्छेद 46 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आरक्षण (सकारात्मक कदम) प्रदान करती है

103 वां संविधान संशोधन (जनवरी 2019)

- ❑ जोड़ा गया -अनुच्छेद 16(6) - EWS के लिए 10% तक नौकरियां
- ❑ जोड़ा गया -अनुच्छेद 15(6) - EWS के लिए शैक्षणिक संस्थानों में 10% तक सीटें (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर)

पात्रता (सरकार द्वारा अधिसूचित, संविधान में नहीं)

- SC/ST/OBC नहीं
- पारिवारिक आय < 8 लाख/वर्ष
- कृषि भूमि < 5 एकड़
- घर < 1000 वर्ग फुट
- नगरपालिका क्षेत्र में आवासीय भूखंड <100 गज
- गैर-नगरपालिका क्षेत्र में आवासीय भूखंड <200 गज

हाल के संवैधानिक संशोधन

- ❑ 102 वां संशोधन : NCBC को संवैधानिक दर्जा **(पेज-11)**
- ❑ 103 वां संशोधन : EWS को 10% आरक्षण
- ❑ 104 वां संशोधन : लोकसभा/विधानसभा में SC/ST के लिए आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाया गया ; लेकिन एंग्लो-इंडियन के लिए नहीं
- ❑ 105 वां संशोधन : राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार फिर से दिया गया **(पेज-56)**

Test yourself

भारत का संविधान गारंटी देता है

- ✓ कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14)
- ✓ प्रतिष्ठा की समानता (17: अस्पृश्यता नहीं, 18: कोई उपाधि नहीं)
- ✓ अवसर की समानता (अनुच्छेद 15 और 16)
- **X** परिणाम की समानता (ऐसी कोई गारंटी नहीं, यह व्यावहारिक नहीं है!)

अनुच्छेद 15	अनुच्छेद 16
लिंग	लिंग
जन्म स्थान	जन्म स्थान, निवास
धर्म	धर्म
जाति	जाति
मूल वंश	मूल वंश , उद्भव

अनुच्छेद 15

निवास स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है ? **गलत**
राज्य को SC/ST/SEBC/OBC/EWS के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है ? **सही**
राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है ? **सही**
राज्य को निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का अधिकार देता है ? **सही**
राज्य को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का अधिकार देता है ? **गलत**

अनुच्छेद 16

निवास स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है ? **सही**
राज्य को निजी क्षेत्र में आरक्षण देने का अधिकार देता है ? **गलत**
राज्य को पिछडे वर्ग को आरक्षण देने का अधिकार देता है ? **सही**
राज्य को SC/ST को परिणामी ज्येष्ठता (Consequential Seniority) के साथ पदोन्नति में आरक्षण देने का अधिकार देता है ? **सही**

OBC आरक्षण

पेज -11 देखें

स्थानीय निकायों में सीटों का आरक्षण

SC और ST	जनसंख्या अनुपात के अनुसार
महिला	न्यूनतम 1/3 20 राज्य महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करते हैं
पिछड़ा वर्ग	राज्य विधायिका कानून बना सकती है*

* स्थानीय सरकार/निकाय द्वितीय-सूची यानी राज्य सूची में है

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

Row after SEC tells collectors to remove OBC quota in Gujarat gram panchayat polls

By: Express News Service

Gandhinagar | July 7, 2022 05:13 IST

NewsGuard

कृष्णमूर्ति केस 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि OBC को आरक्षण देने के लिए, राज्यों को ट्रिपल टेस्ट/शर्तों का पालन करना होगा:

1. पिछड़ेपन पर डेटा इकट्ठा करने के लिए एक आयोग का गठन करें
2. स्थानीय निकायों के लिए आवश्यक आरक्षण का अनुपात निर्दिष्ट करें
3. SC+ST+OBC के लिए आरक्षण, कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं होगा

THE HINDU

The question of OBC reservation in local bodies

The apex court's latest order makes it mandatory that the principles laid down by the Supreme Court must be followed across the country

January 21, 2022 10:42 am | Updated 07:00 pm IST

Prelims 2006

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन को प्रोत्साहित करने के लिए भारत के संविधान में कोई प्रावधान नहीं है।
2. भारत का संविधान पिछड़े वर्ग को परिभाषित नहीं करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

SC directions on hate speech: How courts have read IPC Sec 295A, other provisions

By: Explained Desk

New Delhi | Updated: October 22, 2022 15:07 IST

NewsGuard

The court warned authorities that "any hesitation to act in accordance with this direction will be viewed as contempt of court and appropriate action shall be taken against the erring officers". (Illustration by C R Sasikumar)

हेट स्पीच *(द्वेषपूर्ण भाषण)*

और पढ़ें - मैन्स क्लास 73
https://allinclusiveias.files.wordpress.com/2022/09/class-73-mains-2022.pdf

हेट (घृणा) : वर्ग, जाति, क्षेत्र, धर्म आदि के आधार पर नफरत की प्रबल भावना
हेट स्पीच : मीडिया, सोशल मीडिया, भाषण आदि के माध्यम से दूसरों में नफरत फैलाना
हेट क्राइम : एक समूह के लोगों के खिलाफ हिंसा (लिंचिंग, दंगा, हत्या, गैंगरेप)

संविधान में "**हेट स्पीच**" का उल्लेख है ? **ग़लत**
"**हेट स्पीच**" फ्री स्पीच (वाक् स्वतंत्रता) पर एक उचित प्रतिबंध है? **सही**
IPC/CrPC में "**हेट स्पीच**" को परिभाषित किया गया है? **गलत** (इसे किसी भी कानून में परिभाषित नहीं किया गया है)
हेट स्पीच से निपटने के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है ? **गलत**

IPC के तहत दुश्मनी पैदा करना, नफरत फैलाना आदि दंडनीय हैं ।
समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए दोषी व्यक्ति को RPA 1951 के तहत अयोग्य घोषित किया जा सकता है
IT अधिनियम-2000 की धारा 66A में संचार सेवाओं के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने पर दंड का प्रावधान है

फोन किस लिस्ट में आता है?
लिस्ट-I यानी संघ सूची

फोन टैपिंग

वायरटैपिंग, इंटरसेप्शन, लाइन बगिंग

फोन टैपिंग क्या है?

- ❑ दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच संचार को गुप्त रूप से सुनना।
- ❑ किसके द्वारा विनियमित/नियंत्रित किया जाता है ?
  - भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2)
  - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69
  - सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2009

The Indian EXPRESS Epaper

Premium

Explained: What laws govern tapping a phone; what are the checks in place?

Written by **Deeptiman Tiwary** | New Delhi |
Updated: April 23, 2022 8:20:17 am

कानूनी प्रावधान

- ❑ फोन टैपिंग कौन कर सकता है
  - केंद्र- ED, CBI, IB, NIA, RAW आदि जैसी 10 एजेंसियां।
  - राज्य- राज्य पुलिस
- ❑ फोन टैपिंग की वजह
  - भारत की संप्रभुता और अखंडता
  - विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
  - सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा, आदि
- ❑ फोन टैपिंग का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है
  - केंद्र में गृह सचिव
  - राज्यों में गृह सचिव

दूरसंचार सेवा-प्रदाता (टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स) की भूमिका

- टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को फोन टैपिंग के ऑर्डर दिए जाते हैं।
- वह ऐसे आदेशों का पालन करने के लिए क़ानूनी रूप से बाध्य हैं।

क्या आपको पता था?

- ➢ टेलीकॉम ऑपरेटरों को शामिल किए बिना "ऑफ-एयर फोन-टैपिंग" की जा सकती है!
- ➢ ऐसा करना गैरकानूनी है, और ठीक 10 साल पहले सेना (Army) में यह बहुत बड़ा मसला बन गया था

Hindustan Times Get App

Army to disband VK Singh's snoops

Updated on Aug 23, 2012
02:12 AM IST

A clandestine military intelligence unit — set up by former army chief Gen VK Singh and accused of tapping the phones of top political leaders — is to be shut down.

The so-called 'technical support division' was controlled directly by VK Singh, who had taken on the government over a dispute on his age — a battle he eventually lost in Supreme Court.

दुरुपयोग के खिलाफ उपाय

- समय सीमा केवल 60 दिनों के लिए टैपिंग की अनुमति दी जाती है। समय सीमा बढ़ाई जा सकती है, लेकिन 180 दिनों से अधिक नहीं।
- समीक्षा समिति केंद्र में कैबिनेट सचिव और राज्यों में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में
- लिखित रिकॉर्ड फोन टैपिंग के आदेश और कारण लिखित रूप में बताने होते है
- प्रेस की स्वतंत्रता मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के प्रेस संदेशों को अवरोधित (इंटरसेप्ट) नहीं किया जा सकता है

कुछ और अहम खबरें

The Telegraph

SC pulls off surprise, orders freezing of sedition law use till it's future is decided

New Delhi | Published 11.05.22, 05:59 PM

Polity class-5 pg-49: Sedition
May magazine (discontinued) pg-7: Sedition

ThePrint

'Right to be Forgotten' finds steam in India, high courts seized of multiple petitions

While a 2017 judgment recognised the 'right to be forgotten' as part of 'right to privacy', online platforms argue it can have a bearing on right to information in some cases.

AKSHAT JAIN 24 July, 2022 12:04 pm IST

Polity class-5 pg-52: Right to be forgotten

LiveLaw.in

Private Bill To Implement Uniform Civil Code Introduced In Rajya Sabha

Rahul Garg 10 Dec 2022 10:23 AM

Polity class-5 pg-49: Uniform Civil Code

ThePrint

Amarnath Yatra: UAPA invoked against people, groups for spreading anti-national message

PTI 3 June, 2022 10:02 pm IST

Polity class-5 pg-49: UAPA

THE HINDU

OBC sub-categorisation panel gets 14th extension

January 29, 2023 09:06 pm |

Polity class-1 pg-11: OBC sub-categorization

NewsOnAIR

Aug 05, 2022, 9:08AM

Today is third anniversary of abrogation of Article 370

Polity class-3 pg-23: Article 370

सभी PDF पूरी तरह से निःशुल्क हैं और वेबसाइट पर उपलब्ध हैं https://www.allinclusiveias.com/
पिछली कक्षाओं के वीडियो यहां उपलब्ध हैं https://courses.allinclusiveias.com/learn/2022PT365